28.07.2018

शिलोंग में आयोजित मेघालय मिल्क मिशन कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह का लोगों को सम्बोधन

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

मेघालय राज्य में कृषि एवं सहकारिता को बढ़ावा

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) एक संविधिक निगम है, जिसकी स्थापना सहकारिताओं के माध्यम से आर्थिक विकास करने के लिए एक संसदीय अधिनियम के अंतर्गत 1963 में की गई थी। निगम का मुख्य उद्देश्य कृषकों की आमदनी बढ़ाने हेतु उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाना तथा फसलोत्तर सुविधाएं स्थापित करने हेतु कृषक सहकारिताओं का संवर्धन, सुदृढ़ीकरण तथा विकास करना है । निगम का प्रमुख जोर, कृषिनिवेशों के कार्यक्रमों, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, भंडारण तथा विपणन और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है । गैर फार्म क्षेत्र में निगम का प्रयास समाज के कमजोर वर्गो/ग्रामीण निर्धनों पर विशेष ध्यान सहित हथकरघा, कोश-कीटपालन, कुक्कुट-पालन, मत्स्य-पालन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सहकारिताओं आदि जैसे आय सृजित करने वाले कार्यकलापों के संवर्द्धन की सुविधाओं के साथ सहकारिताओं को तैयार करना है ।

2. निगम ने वर्ष 2017-18 के दौरान निरंतर रूप से न केवल उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन किया, बल्कि 8000 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 275% के महत्वपूर्ण प्रगति के साथ 21,970 करोड़ रूपये की सर्वाधिक विमुक्ति की है ।निगम ने पिछले 4 वर्षों में वित्तीय सहायता की विमुक्ति में 417% की महत्वपूर्ण प्रगति दर रिकॉर्ड की है । एनसीडीसी ने दिनांक 31.03.2018 तक लगभग एक लाख करोड रूपये की संचयी वित्तीय सहायता प्रदान की है । वर्ष 1963 से दी गई लगभग एक लाख करोड रूपये की कुल संचयी सहायता में से रूपये 50738 करोड रूपये, जोकि 50 प्रतिशत से भी उपर है, पिछले 4 वर्षों के दौरान दी गई है । इस अवधि में निगम का एनपीए शून्य रहा है ।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचुर अवसरों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार, एनसीडीसी के माध्यम से राज्य सरकार के साझेदारी में क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिये प्रतिबद्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये केंद्र सरकार ने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिये 500 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है | विगत चार वर्षों में अनेक नवीन परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं जिसमें मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा राज्यों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (ICDP), असम राज्य में जूट उद्योग को बढ़ावा देने एवं सहकारिताओं का कंप्यूटरीकरण की योजना, मेघालय राज्य में दुग्ध वयवसाय को बढ़ावा देने की योजना इत्यादि शामिल हैं | इनके अलावा अनेक नवीन परियोजनायें जैसे सम्पूर्ण असम राज्य के लिये 6000 करोड़ रुपये की आईसीडीपी परियोजना, मणिपुर के सभी जिलों के लिये आईसीडीपी परियोजना इत्यादि जल्द ही प्रारंभ होंगीं|

4. मेघालय एक कृषि प्रधान एवं जनजाति बाहुल्य राज्य है । राज्य के सम्पूर्ण विकास हेतु कृषि एवं कृषि सम्बंधित क्षेत्रों का विकास अत्यंत आवश्यक है जिसमे सहकारिताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं| केंद्र सरकार एनसीडीसी के माध्यम से मेघालय राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी समितियां को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है| सहकारी समितियों के मजबूत होने से रोजगार के नए आयाम खुलेंगे, केंद्र सरकार का किसानों की आय दूना करने का लक्ष्य फलीभूत होगा एवं राज्य में समग्र सम्पन्नता आयेगी|

5. एनसीडीसी ने जून, 2018 में डेरी फार्म, चिल्लिंग सेंटर, दुधारू पशु क्रय एवं मेघालय मिल्क मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण आदि के लिए मेघालय सरकार को 215 करोड़ रुपये लागत की परियोजना स्वीकृत किया है | एक डेरी फार्म यूनिट में 5 गाय, शेड निर्माण, चारा रखने हेतु भंडार गृह, पशुओं की बिमा इत्यादि होंगें जिसकी लागत 9.82 लाख रुपये होगी| ऐसे 2000 यूनिट पूरे राज्य में दिए जायेंगे| इसके अलावा 500 लीटर क्षमता के 79 बल्क मिल्क कूलर्स, 3000 लीटर क्षमता वाले 13 मिल्क टैंकर इत्यादि का भी प्रावधान है| परियोजना में किसानों के प्रशिक्षण हेतु 1 करोड़ रुपये का भी प्रावधान है | यह परियोजना राज्य में दुग्ध वयवसाय को बढ़ावा देने एवं किसानों की आय वृद्धि के लिये अत्यंत मत्वपूर्ण है|

6. डेरी परियोजना के अलवा मेघालय में सम्पूर्ण राज्य के लिये आईसीडीपी परियोजना, प्राथमिक सहकारिताओं का कंप्यूटरीकरण एवं एकीकृत सूअर पालन वैल्यू चेन परियोजना प्रारंभ करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं |

7. राज्य में हस्तकरघा, हस्तशिल्प, आर्गेनिक खेती, वन उत्पादन, बागवानी, फलों एवं सब्बिजयों का प्रसंस्करण, पशुपालन , मुर्गीपालन, मछलीपालन, पर्यटन इत्यादि की असीम संभावनाएं हैं| केंद्र सरकार एनसीडीसी के माध्यम से इन क्षेत्रों में कार्यरत राज्य की सहकारिताओं को सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है|

8. केंद्र सरकार के **मिशन 2022** के साथ निगम ने मिशन **सहकार 2022** को जोड़ा है| जिसके अंतर्गत राज्य में सहकारिता के माध्यम से रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, किसानों की आय में वृद्धि हो एवं उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो तथा राज्य में विकास की गति तीव्र हो, सुनिश्चित करना है| केंद्र सरकार एनसीडीसी के माध्यम से राज्य में सभी स्तर की, प्राथमिक, जिलास्तरीय एवं राज्य स्तरीय सहकारी समितियों के पास आधारभूत संरचना हो, प्रसंस्करण की सुविधा हो, मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग हेतु सहायता उपलब्बध हो एवं सभी सहकारी समितियां कॉमप्यूटरीकृत हों इसके लिए प्रयासरत है| मेघालय राज्य में कृषि एवं सहकारिता के माध्यम से समावेशी विकास को गति मिले इसके लिये केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है|

+++++